जालंधर, बुधवार 8 मई 2024
JALANDHAR, LUDHIANA, AMRITSAR, CHANDIGARH
+91 97814 00247

वंदे भारत 24
भारत के मन की बात

सुविचार

जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल तो बनाना ही पडेगा।

@vandebharat24 vandebharat24news @vandebharat24news www.vandebharat24.com

क्या है 133 करोड़ रुपये के खालिस्तानी चंदे का मामला?

जिसमें केजरीवाल के खिलाफ हुई NIA जांच की सिफारिश

जालंधर (हर्ष शर्मा) : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हद्ध जांच की सिफारिश की है. उन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंडिंग लेने का आरोप है.

एलजी दफ्तर की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को इसे लेकर चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में लिखा गया है कि जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठनों से 16 मिलियन डॉलर (करीब 133 करोड़ रुपये) की फंडिंग मिली थी.

एलजी सक्सेना ने ये सिफारिश ऐसे वक्त की है, जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

वहीं, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और 'साजिश' बताया है. पार्टी ने दिल्ली के एलजी को बीजेपी का 'एजेंट' भी बताया है.

ये पूरा मामला क्या है? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम इसमें कैसे आया? एलजी सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में क्या-क्या आरोप लगाए हैं? समझते हैं...

किसने की थी शिकायत?

इसी साल एक अप्रैल को आशु मोंगिया नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के एलजी सक्सेना

के पास शिकायत दर्ज कराई थी. आशु मोंगिया खुद को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव बताते हैं.

आशु मोंगिया ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे और इनकी जांच की मांग की थी.

मोंगिया ने ये भी आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारा में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी, जिसमें देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई का वादा किया गया था. भुल्लर इस वक्त अमृतसर की एक जेल में बंद है.

भुल्लर का मामला क्या है?

1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके में देवेंद्र पाल भुल्लर को दोषी ठहराया गया है. इस धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई थी.

25 अगस्त 2001 को टाडा कोर्ट ने भुल्लर को फांसी की सजा सुनाई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था.

सजा पर रिव्यू करने वाले दिल्ली सरकार के बोर्ड ने दिसंबर 2023 में भुल्लर की रिहाई को खारिज कर दिया था. बोर्ड ने माना था कि भुल्लर को समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

भुल्लर पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बंद था. जून 2015 में मेडिकल आधार पर उसे अमृतसर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. तब से वो वहीं बंद है.

आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश बताया है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सातों सीटें हार रही हैं और इसी हार के डर से वो घबरा गई है. उन्होंने दावा किया कि इसी मामले में हाईलेवल जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका दो साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर लिखा, एलजी साहब चुनावी मौसम में सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. ये एलजी के संवैधानिक कार्यालय का पूरी तरह से दुरुपयोग है.

क्या-क्या हैं आरोप? 3 प्वॉइंट्स में समझें

1. 133 करोड़ की फंडिंग

- 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपये की फंडिंग ली थी. ये फंडिंग जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराने के वादे के रूप में ली गई थी.
- शिकायतकर्ता ने खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी दिया है, जिसमें वो कथित तौर पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी संगठनों से फंडिंग मिलने का आरोप लगा रहा है.

2. न्यूयॉर्क में सीक्रेट मीटिंग

- एलजी सक्सेना को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि 2014 में जब केजरीवाल अमेरिका की यात्रा पर थे, तब उन्होंने खालिस्तानी नेताओं के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी.
- केजरीवाल और खालिस्तानी नेताओं के बीच ये सीक्रेट मीटिंग न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारा में हुई थी. इस मीटिंग में केजरीवाल ने कथित तौर पर फंडिंग के बदले भुल्लर की रिहाई का वादा किया था.
- शिकायत में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता मुनीष कुमार रायजादा ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल और खालिस्तानी नेताओं की मीटिंग की तस्वीर भी साझा की थी. शिकायतकर्ता का दावा है कि जो तस्वीर साझा की गई थी, वो कथित रूप से रिचमंड हिल गुरुद्वारा की थी.

3. भुल्लर की रिहाई का वादा

- एलजी दफ्तर की ओर से केंद्रीय गृह सचिव भेजी गई चिट्ठी में जनवरी 2014 में केजरीवाल की एक चिट्ठी का हवाला भी दिया गया है. इसमें लिखा है कि केजरीवाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भुल्लर की सजा माफी की मांग को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी.
- जनवरी 2014 में ही सीएम केजरीवाल ने इकबाल सिंह नाम के शख्स को भी एक चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में उन्होंने इकबाल सिंह से कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है.
- इकबाल सिंह आतंकी भुल्लर की रिहाई की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे थे. केजरीवाल से भुल्लर की रिहाई का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था.

अब आगे क्या?

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखी चिट्ठी में इस पूरे मामले की एनआईए जांच कराने की सिफारिश की है. उन्होंने लिखा कि शिकायतकर्ता की ओर से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए गए हैं, उनकी फोरेंसिक जांच की जानी की जरूरत है.

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ

ਜਲੰਧਰ (ਹਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਅਸਤੀਫ਼ਾ' ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫ਼ਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

HAKIM TILAK RAJ KAPOOR HOSPITAL PVT. LTD.
NEAR FOOTBALL CHOWK, JALANDHAR | Call/Whatsapp No. +91-95015-02525
आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयों तथा पंचकर्मा द्वारा हर बीमारी के सफल इलाज के लिए मिलें।
Dr. Nuvneet Kapoor
B.A.M.S., M.D (H.T.R.K.)
Ph.: 0181-5092525
Website : www.hakimtilakraj.in

आवश्यकता पंजाब के हर शहर व कस्बे से
वंदे भारत 24 भारत के मन की बात
के लिए पत्रकारों की जरूरत है। चाहवान सम्पर्क कर सकते है।
मोब. 97814-00247, 97804-00247

S.T COLLEGE OF NURSING & MEDICAL SCIENCES
Recognized by INC, New Delhi, Affiliated by BFUHS, Faridkot & PNRC, Mohali Approved by Govt. of Punjab.
COURSES OFFERED
ANM 2 Years Diploma
GNM 3 Years Diploma
B.Sc (Nursing) 4 Years Degree
D-Pharmacy (Ay.) 2 Years & 3 Months Diploma
10+1 & 10+2 (P.S.E.B)
V.P.O. Mehlanwali, Una Road, Hoshiarpur Pb.
Contact : +91-62841-11519, +91-99145-82525
www.stnursinginstitute.in

जयशंकर ने खोली पोल तो कनाडा को लगी मिर्ची

भारत की टिप्पणी पर देने लगा सफाई

जालंधर (काजल विज) : कनाडा और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्ता जगजाहिर है. भारत समय-समय पर कनाडा की पोल खोलता रहा है. हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की वीजा प्रक्रिया पर सवाल खड़े कि थे. जिसके बाद कनाडा ने की भी प्रतिक्रिया आई है. कनाडा ने जयशंकर के बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि वह देश में प्रवेश करने वाले लोगों के प्रति ढिलाई नहीं बरतता है.

कनाडा को देनी पड़ी सफाई

कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी को खारिज किया कि ओटावा लोगों को देश में प्रवेश देने के मामले में ढिलाई बरतता है. मिलर ने कहा कि छात्र वीजा पर कनाडा में प्रवेश करने वाले लोगों की आपराधिक रिकॉर्ड की अधिकारी जांच करते हैं. विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को कहा था,'हमने उनसे (कनाडाई प्राधिकारियों) कई बार कहा कि वे ऐसे लोगों को वीजा, मान्यता या राजनीतिक क्षेत्र में जगह न दें जो उनके (कनाडा के) लिए, हमारे लिए और हमारे संबंधों में समस्या पैदा कर रहे हैं. लेकिन कनाडा सरकार ने कुछ नहीं किया.'

क्या कहा था एस जशंकर ने?

जयशंकर ने कहा था कि भारत ने

25 लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की थी जिनमें से अधिकांश खालिस्तान समर्थक हैं लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया. उनकी यह टिप्पणी कनाडा के प्राधिकारियों द्वारा तीन भारतीय नागरिकों पर खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद आयी है. बताया गया है कि वे छात्र वीजा पर कनाडा में दाखिल हुए थे. कनाडाई नागरिक निज्जर की 18 जून, 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

हम ढिलाई नहीं बरत रहे..

एडमॉन्टन में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों, करण बराड़ (22), कमलप्रीत सिंह (22) और करणप्रीत सिंह (28) पर शुक्रवार को हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. कनाडा के विशेष टेलीविजन चैनल 'केबल पब्लिक अफेयर्स चैनल' की खबर के अनुसार, जयशंकर की टिप्पणी के बारे में सोमवार को एक सवाल का जवाब देते हुए मिलर ने कहा, 'हम ढिलाई नहीं बरत रहे हैं और भारतीय विदेश मंत्री अपनी राय रखने के हकदार हैं.'

जयशंकर के बयान से कनाडा को लगी मिर्ची

यह पूछे जाने पर कि कनाडाई सरकार ने इस बारे में क्या करने की योजना बनाई है तो उन्होंने कहा, इस बारे में कि भारतीय विदेश मंत्री ने क्या कहा है? उन्हें अपने मन की बात कहने दीजिए. यह सही नहीं है.

उन्होंने कहा कि कनाडा छात्र वीजा पर देश में प्रवेश करने वाले लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करता है. यह पूछे जाने पर कि यह कैसे काम करता है, तो उन्होंने कहा, इसकी जांच करते हैं कि क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है; होता है तो वे नहीं आते हैं.

निज्जर की हत्या की जांच जारी

भारत ने निज्जर को 'आतंकवादी' घोषित किया था. हत्या के सिलसिले में तीन भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद कनाडा में पुलिस ने अतिरिक्त विवरण दिए बिना कहा कि उन्होंने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है. पुलिस ने इसके संकेत दिये कि और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के सहायक आयुक्त डेविड टेबौल ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह गिरफ्तार किए गए तीन लोगों और भारतीय अधिकारियों के बीच कथित संबंधों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि बल 'भारत सरकार के साथ संबंधों की जांच कर रहा है.'

..इसका भारत से कोई लेना-देना नहीं

इस बीच, जयशंकर ने शनिवार को कहा था कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वह ज्यादातर वहां की आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थकों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहा है, 'लॉबी' बना रहा है और एक वोट बैंक बन गया है.

आतंकवादी निज्जर की हत्या का मामला

मिलर ने कहा कि कनाडा इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेता है. उन्होंने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि क्या निज्जर की हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए तीन भारतीय छात्र वीजा पर कनाडा में थे. उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ जानकारी है जिसे वह पुलिस की जांच जारी रहने के चलते इस समय साझा नहीं कर सकते. कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल सितंबर में भारतीय एजेंटों पर निज्जर की हत्या में 'संभावित रूप से' शामिल होने का आरोप लगाया था जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव आ गया था. भारत ने ट्रूडो के आरोपों को 'बेतुका' और 'प्रेरित' बताकर खारिज कर दिया था.

राहुल गांधी देश के सामने आकर बोलें 370 और राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं करेंगे : आचार्य प्रमोद कृष्णम

जालंधर (संदीप मान) : हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मंशा रखते थे। अब इसको लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह बात खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन की सरकार आ जाएगी। इसको रोकना होगा। ऐसे में बताएं कि सनातन और भगवान का विरोधी कौन है। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की मिली-जुली सरकार बनती है, हालांकि, बनेगी नहीं, देश की जनता इस बात को समझ चुकी है, अगर इनकी सरकार बनती है तो राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे, राम मंदिर के फैसले को बदल देंगे। जिस तरह शाहबानो केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बदला था।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पूरी चौकड़ी इस पर काम कर रही है। यह लोग दो फैसले को बदलना चाहते हैं, एक मंदिर और दूसरा आर्टिकल 370। अगर मेरी बात गलत है तो राहुल गांधी आगे आएं और इस पर जवाब दें। देश के सामने आकर बोलें कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू नहीं करेंगे, वो बोलें कि हम राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने इस पर जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उनके मन में चोर है।

इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस बार का वोट राष्ट्र के लिए और अखंड भारत के लिए होना चाहिए।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के पीएम मोदी को एंटी मुस्लिम बताने वाले बयान पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा है कि वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, या कभी नहीं कहा है कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता का सेवक हूं और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं, बल्कि देश का होता है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री भी किसी पार्टी से संबंध रखते हैं।

उन्होंने आगे कहा, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनका हृदय विराट है, वो उनका भी स्वागत करते हैं, जो उनका विरोध करते हैं। विपक्ष पीएम मोदी की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। देश के प्रधानमंत्री को रोज गाली देना और उनका अपमान करना, यह विपक्ष को शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जितने हिंदुओं के हैं, उतने ही मुसलमानों के भी हैं। इसलिए मैं पीएम मोदी के बयान का समर्थन करता हूं।

43 साल पुराने मामले में नहीं बचा कोई गवाह, कांग्रेस को योगी सरकार को देने हैं 2.68 करोड़ रुपये

जालंधर (जसवीर) : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 1981-89 के दौरान राजनीतिक रैलियों में समर्थकों को ले जाने के वास्ते उसके वाहनों को किराये पर लेने के लिए कांग्रेस की प्रदेश इकाई पर 2.68 करोड़ रुपये के उसके दावे की गवाही देने के लिए सेवा में कोई गवाह नहीं बचा है. यूपीएसआरटीसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ से कहा, यह बहुत पुराना मामला है और हमारे पास दावे की गवाही देने के लिए सेवाओं में कोई गवाह नहीं बचा है.

पीठ ने कहा कि वह इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने के बारे में सोच रही है क्योंकि 2.68 करोड़ रुपये की राशि को लेकर उप्र कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) ने आपत्ति जताई है. पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा, कुछ दस्तावेज होंगे, अन्यथा निर्णय कैसे होगा. वे कुछ अधिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं या वे कुछ कम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं. आप निर्देश मांगें और हमें बताएं. प्रसाद ने अदालत से मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का आग्रह किया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस की उप्र इकाई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि राज्य सरकार को 19 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है.

मध्यस्थ की नियुक्ति पर निर्देश लेने को कहा

पीठ ने उप्र कांग्रेस के खिलाफ वसूली कार्यवाही पर रोक के आदेश को बढ़ाने का निर्देश देते हुए मामले को चार सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और प्रसाद से मध्यस्थ की नियुक्ति पर निर्देश लेने को कहा.

BJP को 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया झटका

अल्पमत में आई हरियाणा की सैनी सरकार, समझें आंकड़ों का गणित

जालंधर (हर्ष शर्मा) : हरियाणा के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों के बीजेपी से अलग होने के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है. दरअसल बीजेपी सरकार के पास जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद और अलग होने के बाद 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था. वर्तमान में नायब सैनी सरकार को 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें भाजपा के 41 ,हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक गोपाल कांडा और छह निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था.

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रणजीत चौटाला पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं. इसके बाद यह आंकड़ा बीजेपी के पास 46 का रह गया था. वहीं तीन निर्दलीय विधायकों में भी अपना समर्थन वापस ले लिया है. उनमें चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ,नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन शामिल हैं. सरकार के पास इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन रह गया है.

समझें सीटों का समीकरण : हालांकि अगर नायब सैनी चुनाव जीत जाते हैं तो यह आंकड़ा 44 हो जाएगा लेकिन फिर बहुमत की संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी जो सरकार के पास नही है. वर्तमान परिस्थितियों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 88 है. वहीं सरकार के पास अभी 43 विधायकों का समर्थन है. यानी सरकार अल्पमत में है. हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास 30 विधायक, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं. बीजेपी के 40 विधायक हैं. जबकि निर्दलीयों की संख्या 7 से 6 हो चुकी है क्योंकि रणजीत चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं. एक इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अभय चौटाला है.

6 महीने तक नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव

तीन निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया है जबकि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले ही सरकार से अलग है.

ऐसे में अगर भविष्य में विधानसभा में विश्वास मत लाया जाता है तब सरकार के लिए मुसीबत की घड़ी खड़ी हो सकती है. लेकिन, कांग्रेस बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आई थी जो ध्वनि मत से गिर गया था और सरकार जीत गई थी इस आधार पर अब 6 महीने तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जिससे बीजेपी खुद को राहत महसूस कर सकती है.

US के होटल में मीटिंग, आतंकी भुल्लर की रिहाई का वादा

134 करोड़ की खालिस्तानी फंडिंग, अब कौन सी बड़ी मुसीबत में फंसे केजरीवाल?

जालंधर (हर्ष शर्मा) : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई और बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एलजी विनय सक्सेना ने आतंकी जांच की सिफारिश की है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा है। ये पूरा आरोप 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर फंड लेने का है। हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टी के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश किया जाना अपने आप में बड़ी घटना है। वजह ये है कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से 16 मिलियन डॉलर की फंड लेकर सरकार में आने पर सजा माफ करने की बात है। आपको याद होगा सिख फॉर जस्टिस वाला आतंकी गुरुवतपंत सिंह पन्नू जिसके अक्सर गीदड़भभकी वाले वीडियो सामने आते रहते है। जिसमें वो कभी भारत को धमकी देता तो कभी खालिस्तान के सपोर्ट की बातें करता नजर आता है। पन्नू ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के अमेरिका दौरे के दौरान उससे मुलाकात हुई थी व उसे 16 मिलियन डॉलर यानी 134 करोड़ रुपए सिख फॉर जस्टिस की तरफ से दिया गया था। ये दावा पन्नून की तरफ से किया गया था। इस वीडियो में पन्नू ने कुछ फुटेज इस्तेमाल किए थे जिसमें सिख समुदाय के कुछ लोगों के साथ अमेरिका के होटल में अरविंद केजरीवाल मीटिंग करते नजर आए थे। उस फुटेज में अरविंद केजरीवाल की बगल में मुनीष रायजादा बैठे नजर आए। पेशे से डॉक्टर रायजादा अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में शामिल भी हुए थे।

अरविंद केजरीवाल पर क्या है 'खालिस्तानी फंडिंग' का आरोप?

एलजी की तरफ से शिकायत में एक वीडियो का हवाला दिया गया है जिसमें कथित तौर पर सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नून को दिखाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि आप को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन डॉलर की भारी फंडिंग मिली। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि 2014 में अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में खालिस्तानी समर्थक सिखों के साथ एक गुप्त बैठक में भाग लिया था। इस बैठक के दौरान, केजरीवाल ने कथित तौर पर खालिस्तानी गुटों से आप को वित्तीय सहायता के बदले में एक दोषी आतंकवादी देवेंदर पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने का वादा किया था।

केजरीवाल से पत्र मिलने के बाद समाप्त कर दिया था अनशन

शिकायत में अरविंद केजरीवाल द्वारा इकबाल सिंह को लिखा गया एक पत्र शामिल है जिसमें आप नेता ने कथित तौर पर कहा है कि उनकी सरकार इस मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखती है और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। सक्सेना ने पत्र में कहा कि इसमें आगे उल्लेख है कि दिल्ली सरकार पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश कर चुकी है और एसआईटी के गठन आदि सहित अन्य मुद्दों पर काम करेगी। उस समय की समाचार रिपोर्टों के अनुसार, इकबाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे थे।

बंद कमरे में बैठक

शिकायत एक्स पर एक पूर्व आप कार्यकर्ता द्वारा किए गए कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्टों की ओर भी इशारा करती है। उन्होंने 2014 में रिचमंड हिल गुरुद्वारे में सिख नेताओं के साथ केजरीवाल की एक तस्वीर साझा की थी। डॉ मुनीश कुमार रायज़ादा के ट्वीट में दावा किया गया कि सार्वजनिक बैठकों के अलावा, केजरीवाल ने बंद कमरे में बैठकें कीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, गुरुद्वारे में खालिस्तान समर्थक सिख नेताओं के साथ चर्चा। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच सहित जांच की आवश्यकता है, सक्सेना ने कहा है। पत्र में कहा गया है कि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से प्राप्त राजनीतिक फंडिंग से संबंधित है।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜਾਂ ਰਾਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ, 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਹਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਬਦਲ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਹਲਕਾ ਬਹਾਦਰ ਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ, ਸਹਾਇਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਐਮ. ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸਿਪ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਜਾਮਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਕੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 89/19 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਐਮ. ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ-ਬਾਜ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਫਰਜੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜੇ ਮੌਕੇ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਪਾਸ ਆੜ-ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਜਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜਾ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਮੁਲਜਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਪਰ 122 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਲਿਮਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜਾਅਲੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਪਰ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

S.T HOSPITAL
& Test Tube Baby Centre
Near Football Chowk, Jalandhar.
Mob.: 99154-02525, 0181-5042525
www.sthospital.in

अब हर घर गूँजेंगी खुशियों की किलकारियाँ
IUI | IVF | ICSI
विधियों द्वारा पुरुषों तथा महिलाओं के बाँझपन का उपचार किया जाता है
Dr. Asheesh Kapoor
M.B.B.S., P.G.D.S. (USA)
Fertility & Sex Specialist
Dr. Rimmi Mahajan
M.B.B.S, M.D. (Obs & Gynae)
Fellowship in Rep. Med. (Spain)

फिरोजपुर की पिच पर रोचक हुआ मुकाबला

कांग्रेस ने खोल दिए पत्ते; अब बीजेपी किसपर लगाएगी दांव?

जालंधर (दीपांशु चोपड़ा) : आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने भी लंबे इंतजार के बाद फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। सुखबीर सिंह बादल के हाथों पिछले लोकसभा चुनावों में हारे शेर सिंह घुबाया पर एक बार फिर भरोसा जताया है।

जिलाध्यक्ष कुलबीर सिंह जीरा को खडूर साहिब सीट पर उतारने के बाद कांग्रेस को दमदार प्रत्याशी की जरूरत थी। हालांकि, पूर्व आईपीएस अधिकारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों को पार्टी में शामिल करने के बाद कांग्रेस में ये चर्चा जरूर शुरू हुई थी कि वे पार्टी प्रत्याशी बन सकते हैं। लेकिन फिरोजपुर लोकसभा चुनाव में उनका आधार ऐसा नहीं था कि वे मजबूत प्रत्याशी साबित हो पाते।

घुबाया का पुराना अनुभव है, दो चुनावों में वे दिग्गजों को हरा चुके हैं, यही बात उनके पक्ष में मजबूत रही है। एक दिन पहले ही घुबाया ने जिस प्रकार फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, उसी समय से ये माना जाने लगा था कि घुबाया पर ही पार्टी दोबारा दांव खेल सकती है। हुआ भी वही आखिरकार मंगलवार को पार्टी ने उन्हें आधिकारिक रूप से प्रत्याशी घोषित कर दिया।

घुबाया के आने से रोचक हुआ 'फिरोजपुर' का मुकाबला

लेकिन मंगलवार को आखिरकार कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशी को लेकर चल रहीं अटकलों पर विराम लगा दिया है। घुबाया के आने से अब फिरोजपुर लोकसभा सीट की स्थिति रोचक बनेगी, अभी तक आम आदमी पार्टी ने काका बराड़ के रूप में जो प्रत्याशी की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में वे नया चेहरा हैं। हालांकि, विधानसभा क्षेत्र मुक्तसर साहिब से विधायक हैं, लेकिन लोकसभा का दायरा नौ गुना ज्यादा बड़ा है, घुबाया तीन बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में पूरी विधानसभा क्षेत्र में वे

जाना पहचाना चेहरा हैं। उन पर कोई दाग भी नहीं है।

भाजपा भी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार कर रही थी, अब किसी भी समय में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में रमिंदर आवला की घोषणा हो सकती है। अकाली दल की टिकट पर शेरसिंह घुबाया साल 2009 व 2014 में फिरोजपुर से लोकसभा पहुंच चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को चुनाव में बराया था, इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के ही एक अन्य दिग्गज जगमीत बराड़ को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। इस बार भी उनका दावा शुरू से ही मजबूत माना जा रहा था।

भाजपा किस पर लगाएगी दांव?

फिरोजपुर लोकसभा सीट पर अब सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार कर रही थी। भाजपा को डर था कि अगर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के पूर्व विधायक रमिंदर आवला के नाम की घोषणा कर दी तो पार्टी के दूसरे प्रबल दावेदार राना गुरमीत सिंह सोढी पार्टी से विद्रोह कर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब ये संभावना भी खत्म हो गई।

ऐसा भी माना जा रहा है कि अभी भी भाजपा के प्रत्याशी को लेकर दिल्ली में पेच फंसा नजर आ रहा है। उधर, गुरमीत सिंह सोढ़ी की दावेदारी भी अभी कमजोर नहीं है। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर पार्टी रमिंदर आवला को अपनी प्रत्याशी बनाकर जीतने का लक्ष्य निर्धारित करती है तो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, पार्टी उनकी अनदेखी नहीं कर सकती है। उन्हें फिरोजपुर लोकसभा चुनाव की रणनीति में भी शामिल किया जा सकता है।

दुबई में जालंधर के युवक की हत्या, गुरुद्वारे से लौटते समय पंजाबी युवकों ने ही किया हमला

जालंधर (नितिका) : जालंधर कैंट से सटे जमशेर खास के पत्ती सेखों के रहने वाले 34 वर्षीय युवक की दुबई में झगड़े के बाद पंजाबी युवकों ने तेजधार हथियार से वारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पंकज डौल पुत्र बलविंदर के रूप मे हुई है।

पंकज के साथ काम करने वाले साथियों ने रात करीब साढ़े नौ बजे इसकी जानकारी छोटे भाई गुरप्रीत डौल उर्फ गोपी को दी थी। पंकज की मौत के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है।

जानकारी के अनुसार पंकज डौल रविवार को दुबई के अलकोज में स्थित एक गुरुद्वारा से माथा टेक कर वापस लौट रहा था। इस दौरान कुछ पगड़ीधारी युवकों का पंकज के

साथ मामूली विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि उक्त युवकों ने पंकज पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए थे। खून से लथपथ पंकज क्राइम सीन पर तड़पता रहा। कुछ देर बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

पीछे आ रहे पंकज के साथियों ने उक्त आरोपियों को रोकने की कोशिश की, मगर आरोपी वहां से फरार हो गए थे। जिसके बाद जांच के लिए मौके पर अलकोज सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद पुलिस ने उक्त हत्यारों को सिटी से गिरफ्तार कर लिया था।

शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ी, अपनी उम्मीदवारी छोड़ी

जालंधर (हिमांशु) : पंजाब में 2017 से चुनावी तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रही शिरोमणि अकाली दल को सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश – चंडीगढ़ में झटका लगा, जब उसके उम्मीदवार हरदीप सिंह सैनी ने पार्टी छोड़ दी और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।

चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर श्री सैनी ने कहा कि वह चंडीगढ़ की एकमात्र सीट के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी से समर्थन की कमी से नाराज थे।

पार्टी का टिकट लौटाने और छोड़ने के पीछे का कारण पार्टी की चंडीगढ़ इकाई और हमारे प्रति उदासीनता है। पार्टी नेतृत्व ने वादा किया कि वे अभियान का ध्यान रखेंगे. एक पखवाड़ा से ज्यादा हो गया लेकिन पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता यहां नहीं आया, कोई समर्थन नहीं है. यह कोई नगर निगम चुनाव नहीं है जिसे अकेले लड़ा जा सके। सांसद का चुनाव पार्टी स्तर पर लड़ा जाता है, उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा।

वर्तमान में चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद हरदीप सिंह ने कहा कि वह किसी दबाव में नहीं हैं और उन्होंने राज्य पार्टी इकाई के सदस्यों से परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अकाली दल पहली बार चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहा है और पार्टी के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव से पहले इस निर्वाचन क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है, फिर भी उनका रवैया उदासीन रहा है।

पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में 1 जून को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय टंडन और कांग्रेस के मनीष तिवारी शहर से चुनावी मैदान में प्रमुख दावेदार हैं।